1,486 लोगों को 2001 से 2015 के बीच मृत्युदंड सुनाया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के मुताबिक, केवल पांच फीसद (73) अपील की प्रक्रिया के बाद भी मृत्युदंड की कतार में थे।

निर्भया के दोषियों के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी, 3 मार्च को होगी फांसी

चारों को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश, दोषी मुकेश ने भी खुद को वकील से किया अलग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ है। सोमवार को निर्भया के परिजनों और दिल्ली सरकार की अर्जी पर पटियाला हाउस की एक अदालत ने चारों दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी देने का आदेश जारी किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश की तरफ से बताया गया कि वह नहीं चाहता है कि अब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसका प्रतिनिधित्व करें। इस पर वृंदा ग्रोवर ने अदालत से अपील की कि उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए। इस दलील को मानते हुए जज ने वृंदा ग्रोवर को केस से मुक्त कर दिया। इसके बाद मुकेश की मां ने एक अर्जी दायर कर वकील मुहैया कराने की मांग की। जज ने इस अर्जी पर अधिवक्ता रवि काजी को ही मुकेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा। रवि काजी को पिछली सुनवाई पर दोषी पवन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि पवन ने अपने पुराने अधिवक्ता एपी सिंह से खुद को अलग कर लिया था।

सुनवाई के दौरान विनय के अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत को बताया कि वह तिहाड़ जेल में 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर है। इस पर जज ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि विनय का ध्यान रखा जाए। साथ ही अदालत को बताया गया कि विनय पर जेल में हमला हुआ था और उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। चोट की वजह से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती। वहीं अक्षय के परिजनों ने अधूरी दया याचिका दायर कर दी है। ऐसे में उसमें सुधार कर फिर से दायर किया जाना है।

पवन के अधिवक्ता रवि काजी ने अदालत में दलील दी कि अदालत ने सभी उपाय करने के लिए दोषियों को सात दिन का समय दिया था, लेकिन पवन अभी तक अपनी क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दायर नहीं कर पाया। क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं थे। अब उनकी पवन के साथ बैठक है और उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन दायर करेंगे। हालांकि तमाम दलीलों के बाद अदालत ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया।

दोषियों का वजन जेल प्रशासन के लिए अहम : डेथ वारंट के बाद जेल प्रशासन की नजर अब निर्भया के दोषियों के स्वास्थ्य पर है। जेल प्रशासन को दोषियों के डेथ वारंट जारी होने की जानकारी मिलते ही जेल संख्या तीन के हाई सिक्योरिटी सेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शाम में चारों दोषियों का वजन किया गया, जिसे इनकी फाइलों में दर्ज किया गया। अब रोजाना सुबह-शाम इनका वजन किया जाएगा। रोजाना इनकी काउंसिलिंग भी की जाएगी। बता दें कि जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी की सजा पर अमल तभी हो सकेगा, जब ये शारीरिक व मानसिक तौर पर पूरी तरह फिट रहेंगे। स्वास्थ्य जांच के दौरान अन्य बातों के अलावा इनके वजन पर नजर रखी जा रही है। वजन के हिसाब से यह तय होगा कि किस दोषी को फंदे से कितना नीचे लटकाया जाएगा।

निर्भया दुष्कर्म कांड के दोषी (बाएं से) मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की फाइल फोटो। एपी

आज खुल सकता है फांसी घर का ताला

मंगलवार को फांसी घर के मुख्य दरवाजे पर जड़ा ताला खुलने की पूरी संभावना है। पिछली बार जल्लाद द्वारा किए गए ट्रायल के बाद फांसी घर को बंद कर दिया गया था। अब जबकि डेथ वारंट जारी हो गया है और फांसी की तारीख निश्चित हो चुकी है। मंगलवार को अधिकारियों की टीम वहां के इंतजामों का जायजा लेगी, इसकी संभावना है।

मध्यस्थों से बातचीत के लिए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी तैयार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट द्वारा नियुक्त किए मध्यस्थों से बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर सरकारी अधिकारियों से भी वार्ता को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सोमवार सुबह से ही शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी बेहद उत्सुक नजर आए।

कोर्ट ने जब कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो धरने पर बैठीं महिलाओं ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। धरने पर बैठीं दादी बिलकिस ने मंच से दूसरी महिलाओं को इस निर्णय के बारे में जानकारी दी। दादियों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल से वह भी बात करेंगी और अपनी बात विस्तार से रखेंगी। शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को मध्यस्थ नियुक्त किया। इस पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिमंडल और सरकारी अधिकारियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस से वह बात नहीं करेंगे।

कोर्ट में सुनवाई से पहले शाहीन बाग में मामूली सी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही सुनवाई पूरी हुई लोगों का हुजूम एकदम से मंच के पास पहुंचने लगा। हर कोई एक-दूसरे से कोर्ट के फैसले पर चर्चा करता हुआ नजर आया।

दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में महिलाओं का धरना सोमवार को भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ फैसला सुनाने का कोई फर्क नही पड़ा। प्रेट्र

शरजील इमाम ने ही जामिया के छात्रों को दंगे के लिए उकसाया : पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पुलिस को शरजील की एक दिन की रिमांड मिली, देशद्रोह में भी है आरोपित
- पिछले साल 13 दिसंबर को जामिया में प्रदर्शन के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 15 दिसंबर को जामिया इलाके में शरजील के भाषणों की वजह से ही हिंसा भड़की थी। सोमवार को दंगे भड़काने के आरोपित शरजील इमाम को तिहाड़ जेल से साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड की मांग को मंजूर किया। जांच में दिल्ली में दंगा करने के लिए उकसाने की बात सामने आने पर क्राइम ब्रांच ने अब उसके खिलाफ दंगा करने के लिए उकसाने व आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा भी दर्ज कर किया है। देश के खिलाफ आपत्तिजनक व भड़काऊ भाषण देने का वीडियो वायरल होने पर क्राइम ब्रांच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देशद्रोह के आरोपित शरजील के खिलाफ पहले देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसके पैतृक गांव जहानाबाद से उसे गिरफ्तार किया था। शरजील के खिलाफ दिल्ली, असम व अलीगढ़ समेत कई राज्यों में मुकदमा दर्ज है। अभी केवल दिल्ली पुलिस ने ही उससे दो बार लंबे समय के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। वह अभी तिहाड़ जेल में ही बंद था।

डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश देव ने बताया कि 13 दिसंबर को जामिया मिल्लिया के छात्रों व स्थानीय लोगों ने जब नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पहली बार प्रदर्शन किया था तब शरजील उसमें शामिल था। उसने उक्त प्रदर्शन के दौरान छात्रों व स्थानीय लोगों को दंगा करने के लिए उकसाने के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। शरजील का भाषण सुनकर ही लोग उग्र हो गए थे। अगले दिन 14 दिसंबर को भी छात्रों व स्थानीय लोगों ने जामिया, शाहीनबाग व आसपास के इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया था। पुलिसकर्मियों ने हाथापाई व मारपीट की थी।

इसके बाद 15 दिसंबर को छात्रों व स्थानीय लोगों ने जामिया इलाके में जमकर हिंसा और तोड़फोड़ की थी। जिसके बाद दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ तीन केस दर्ज किए थे। विस्तृत जांच के लिए पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था। उक्त मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी 40 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपितों में एक ने पूछताछ में बताया कि 13 दिसंबर को शरजील ने जामिया के बाहर भड़काऊ भाषण दिया था। उसके बयान को आधार बनाकर व उस आरोपित को गवाह बनाते हुए क्राइम ब्रांच ने शरजील के खिलाफ दंगे भड़काने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। सुबूत के तौर पर क्राइम ब्रांच ने शरजील के 13 दिसंबर के वीडियो को हासिल कर लिया है। जामिया मिल्लिया में छात्रों व स्थानीय लोगों को भड़काने के बाद वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी गया और वहां भी भड़काऊ भाषण दिया था।

मुसलमानों ने लिखी चिट्ठी, कब्रिस्तान पर न बनाएं मंदिर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली बैठक होने वाली है। इस बीच अयोध्या के कुछ मुसलमानों ने वकील के जरिये ट्रस्ट को पत्र भेजकर मुसलमानों की कब्रों पर राम मंदिर नहीं बनाए जाने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि आज भले ही वहां कब्रें न दिख रही हों, लेकिन वहां 4-5 एकड़ जमीन पर मुसलमानों की कब्रें थीं। ऐसे में वहां मंदिर की नीव कैसे रखी जा सकती है?

करीब नौ मुसलमानों ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 1993 में अयोध्या में अधिगृहीत की गई 67 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी है। उस जमीन पर मुसलमानों की कब्रें थीं। वह जमीन करीब 4-5 एकड़ है। केंद्र सरकार ने इस पहलू पर विचार नहीं किया कि मुसलमानों के कब्रिस्तान पर भव्य राममंदिर नहीं बन सकता। यह धर्म के विरुद्ध है। पत्र में ट्रस्टियों से कहा गया है कि आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं और आपको हिंदू धर्म की जानकारी है। आप लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या राम मंदिर की नींव मुसलमानों की कब्रों पर रखी जा सकती है? ट्रस्ट के प्रबंधन को यह फैसला करना होगा। ट्रस्ट से आग्रह किया गया है कि 4-5 एकड़ जमीन जहां ढहाए गए विवादित ढांचे के आसपास कब्रें थीं, उस जगह का प्रयोग न किया जाए। भले ही आज वहां कब्रें नजर नहीं आ रही हों लेकिन इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि 1949 को जब वहां अंदर मूर्तियां रखी गईं से लेकर 1992 तक वह जगह अलग तरह से प्रयोग होती रही है। ट्रस्टियों को भेजा गया यह पत्र 15 फरवरी का लिखा हुआ है।

बैठक में बुलाए गए महंत नृत्यगोपालदास, सदस्य बनाए जाने के कयास

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं रामनगरी की शीर्ष पीठ मणिरामदास जी की छावनी के महंत नृत्यगोपालदास (85) को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक बुधवार को दिल्ली में प्रस्तावित है। हालांकि, महंत नृत्यगोपालदास ट्रस्ट में शामिल नहीं हैं और इसको लेकर स्थानीय संतों का असंतोष भी मुखर है। ऐसे में बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाना, इस संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है कि श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में उन्हें शामिल किया जा सकता है।

बैठक के दो दिन पूर्व सोमवार को ट्रस्ट के तीन सदस्य जगद्गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, अयोध्या राजपरिवार के मुखिया बिमलेंद्रमोहन मिश्र एवं डॉ. अनिल मिश्र की महंत नृत्यगोपालदास से मुलाकात इसी संभावना से जोड़ कर देखी जा रही है। महंत नृत्यगोपालदास की गणना मंदिर आंदोलन के प्रमुख संवाहकों में होती है। साढ़े तीन दशक पूर्व मंदिर आंदोलन की शुरुआत से ही नृत्यगोपालदास आंदोलन के अहम किरदार के रूप में सामने आए। साधन-सुविधा युक्त उनका आश्रम और उनके लाखों विरक्त-गृहस्थ शिष्य भी मंदिर आंदोलन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए।

कई वर्षों तक मंदिर आंदोलन के संरक्षक की भूमिका में रहे नृत्यगोपालदास 2003 में रामचंद्रदास परमहंस के साकेतवास के बाद रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं।

ट्रस्ट गठन में उनकी अनुपस्थिति ने सभी को चौंकाया। यही वजह थी कि एलान के अगले दिन ही स्थानीय संतों का असंतोष उभरा। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महंत नृत्यगोपालदास एवं उनके उत्तराधिकारीमहंत कमलनयनदास से वार्ता कर दखल दिया। ट्रस्ट में न्यास अध्यक्ष को शामिल किए जाने का आश्वासन दिया था। तभी से यह कयास हैं कि श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महंत नृत्यगोपालदास को शामिल किया जा सकता है।

यूपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में 6320 अभ्यर्थी सफल

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

- उप्र लोक सेवा आयोग ने घोषित किया प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट
- 15 दिसंबर को प्रदेश के 19 जिलों में एक साथ कराई गई थी परीक्षा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सोमवार देर रात घोषित रिजल्ट में 6320 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित पदों की विशिष्ट अर्हताओं व अभ्यर्थियों के ऑनलाइन दावों को देखते हुए सामान्य चयन का रिजल्ट सात अलग-अलग ग्रुपों में जारी किया है। इसी के साथ एसीएफ व आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2019 का भी परिणाम जारी किया गया है।

यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस), सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (आरएफओ) प्रारंभिक परीक्षा 2019 बीते 15 दिसंबर को एक साथ कराई थी। आयोग ने 16 अक्टूबर 2019 को पीसीएस के 309, एसीएफ के दो व आरएफओ के 53 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, 13 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। पीसीएस के पदों की संख्या बढ़कर अब 529 हो गई है। 19 जिलों में 1166 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा कराई गई। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षा परिणाम से संबंधित अंतिम उत्तरकुंजी, प्राप्तांक व श्रेणीवार, पदवार कटऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 20 अप्रैल से प्रस्तावित है। आयोग ने इस परीक्षा के दो माह पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जल्द ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन जाएंगे और फिर अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी होगा। इसके लिए आयोग अलग से विज्ञप्ति जारी करेगा।

देशद्रोह मामले में इंजीनियरिंग कॉलेज के तीनों कश्मीरी छात्र दोबारा गिरफ्तार

हुबली, प्रेट्र : देशद्रोह के आरोपित तीन कश्मीरी छात्रों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 169 के तहत बांड भरवाकर छोड़े जाने के मामले में कर्नाटक पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। भारी विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस को तीनों आरोपितों को सोमवार को दोबारा गिरफ्तार करना पड़ा।

कर्नाटक के हुबली में स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले तीनों छात्रों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन पर पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गत वर्ष 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हो गया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।

पुलिस ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 169 के तहत बांड भरवाकर तीनों आरोपितों को छोड़ दिया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस को निशाने पर ले लिया था। दक्षिणपंथी संगठनों ने पुलिस मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने भी तीनों आरोपितों को छोड़े जाने की कड़ी आलोचना की थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने भी इस संबंध में अधिकारियों से बात की थी।

हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त आर. दिलीप ने बताया, 'आरोपित तीनों कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।'

देशद्रोह के आरोप में तीन कश्मीरी छात्रों को दोबारा गिरफ्तार कर कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को उन्हें हुबली जिला अदालत में पेश किया। प्रेट्र

एकल अभियान के जरिये गांव-गांव पहुंचेगा रामराज : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

एकल अभियान के परिवर्तन कुंभ का शुभारंभ करते हुए उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा शासन में देश व प्रदेश में आ रहे परिवर्तन पर भी रोशनी डाली। संस्था के सेवाकार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसे ही विराट रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। यदि एकल अभियान के माध्यम से शासन की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचेंगी तो गांव-गांव रामराज का मार्ग प्रशस्त होगा। डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन एकल अभियान के परिवर्तन कुंभ का उद्घाटन समारोह था।

बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एकल अभियान इस बात को साबित करता है कि हमारे यहां सेवा किसी सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि हमें सनातन परंपरा से मिली है। अशोक सिंहल ने जिस एकल अभियान का बीजारोपण किया था, आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप एक लाख की संख्या पार कर सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रसार में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है।

योगी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में दी गई सुविधाओं की गति अगर 1947 से होती तो आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसे इन योजनाओं की जरूरत होती। पूर्व की सरकारों के पास विजन नहीं था। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के आंकड़े रखने के साथ ही कहा कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यह वनवासी जीवन को मान्यता देने का काम भी है।

योगी आदित्यनाथ फाइल

गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का किया जाएगा भव्य स्वागत, सात घेरे की सुरक्षा में तैनात होंगे 25,000 जवान और अफसर

ट्रंप की सुरक्षा कार लेकर पहुंचा वायुसेना का विमान

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुजरात की धरा पर भव्य स्वागत किया जाएगा। सोमवार को अमेरिकी वायुसेना का विमान ट्रंप के सुरक्षा काफिले की कार लेकर अहमदाबाद पहुंच गया।

मुख्यमंत्री रूपाणी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति 24 फरवरी को वाशिंगटन से सीधे अहमदाबाद पहुंचेंगे। वह करीब तीन घंटे यहां रुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वह गांधी आश्रम आएंगे और दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। स्टेडियम में एक लाख से अधिक लोग ट्रंप का भव्य स्वागत करेंगे। उनके स्वागत में गुजरात के महिला-पुरुष और बच्चे पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। ट्रंप की यात्रा के इस दौरान अहमदाबाद का वायुक्षेत्र नो-फ्लाई जोन रहेगा। अहमदाबाद आने वाली सभी उड़ानों को वडोदरा डायवर्ट किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अहमदाबाद दौरे से एक सप्ताह पहले उनकी सुरक्षा में लगा अमेरिकी वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान सोमवार को अहमदाबाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। ट्रंप की सुरक्षा कार फोर्ड डी00074 भी यहां पहुंच गई।

इस यात्रा के दौरान ट्रंप और मोदी सुरक्षा के सात घेरों में रहेंगे। गुजरात सरकार ने सुरक्षा में 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं, इनमें 25 आइपीएस शामिल हैं। गांधी आश्रम से मोटेरा स्टेडियम तक सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए जल्द ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ भारत के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) और नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड (एनएसजी) की टीमें भी यहां पहुंचेंगी।

गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा काफिले का वाहन। इसे ट्रंप के भारत दौरे के मद्देनजर अमेरिकी वायुसेना के विमान से यहां लाया गया। जागरण

नमस्ते ट्रंप की थीम पर होगा स्वागत

ट्रंप की यात्रा के मद्देनजर साबरमती आश्रम और मोटेरा स्टेडियम को सजाने संवारने का काम पूरी गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा की थीम 'नमस्ते ट्रंप' रखी गई है। उनकी यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए रूपाणी सोमवार को खुद मोटेरा स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा, बीसीसीआइ सचिव जय शाह, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनराज नथवाणी आदि भी मौजूद थे।

ट्रंप की यात्रा की तैयारियां 'गुलाम मानसिकता' का प्रदर्शन : शिवसेना

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की यात्रा की तैयारियां भारतीयों की गुलाम मानसिकता प्रदर्शित करती हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में लिखा है कि ट्रंप की भारत यात्रा बादशाह की यात्रा की तरह है। संपादकीय के मुताबिक, 'स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश राजा या रानी भारत जैसे अपने गुलाम देशों की यात्रा किया करते थे। ट्रंप के आगमन के लिए करदाताओं के पैसे से उसी तरह की तैयारियां की जा रही हैं।' ट्रंप के यात्रा मार्ग पर झुग्गियों को छिपाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा दीवार बनवाने के लिए शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। पार्टी ने कहा, 'पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने एक बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था जिसका लंबे समय तक मजाक उड़ाया गया। अब ऐसा लगता है कि मोदी की योजना गरीबी छिपाओ की है। अहमदाबाद में बनाई जा रही ऐसी दीवार लिए क्या कोई वित्तीय आवंटन किया गया है? क्या देशभर में ऐसी दीवारें बनाने के लिए अमेरिका भारत को कर्ज देने का प्रस्ताव करने जा रहा है? हमने सुना है कि ट्रंप अहमदाबाद में सिर्फ तीन घंटे के लिए रहेंगे, लेकिन दीवार के निर्माण से राज्य के खजाने पर करीब 100 करोड़ का बोझ पड़ रहा है।' शिवसेना ने दावा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सिर्फ एक राजनीतिक सामंजस्य है।

झुग्गियों को छिपाने के लिए दीवार बनाना अमानवीय : कांग्रेस

मुंबई, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से पहले अहमदाबाद में झुग्गी बस्ती को छिपाने के लिए दीवार बनाने के भाजपा सरकार के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना करते हुए इसे अमानवीय करार दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने कहा कि यह दीवार दिखाती है कि मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान गुजरात के विकास के नरेंद्र मोदी के दावे झूठे थे। इस बीच, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज गुजरात कांग्रेस ने 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है। पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार समुचित कदम उठाए।